Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com
ISSN:2584-105X Pg. 223 - 231

राजनीतिक विचारधाराओं का राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों पर प्रभाव का विश्लेषण

Dr. Sarojani Singh
Assistant Professor.
Maharishi University of Information Technology, Lucknow
Dr. S.P Singh
Assistant Professor.
Kalicharan P. G. College, Lucknow

Received: 27/06/2025
Accepted: 28/06/2025
Published: 30/06/2025

Abstract

यह शोध पत्र यह विश्लेषण करता है कि राजनीतिक विचारधाराएं किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के निर्माण, उनके विषयवस्तु और क्रियान्वयन को आकार देती हैं। भारत को एक अध्ययन के रूप में लेते हुए, यह शोध दर्शाता है कि कैसे विभिन्न वैचारिक ढांचे—समाजवाद, नवउदारवाद, राष्ट्रवाद और प्रगतिशील सोच—स्वतंत्रता के समय से लेकर वर्तमान तक शैक्षिक सुधारों को प्रभावित करते रहे हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य शिक्षा को एक ऐसा उपकरण और उत्पाद के रूप में समझने के लिए एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना है, जिसे राजनीतिक शासन द्वारा आकार दिया जाता है।राजनीतिक विचारधाराएं शिक्षा को प्रभावित करती हैं—पाठ्यक्रम से लेकर वित्तपोषण तक। उदारवाद (Liberalism) व्यक्तिगत अधिकारों और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, रूढ़िवाद (Conservatism) पारंपरिक मूल्यों पर जोर देता है, और समाजवाद (Socialism) सार्वभौमिक पहुंच की वकालत करता है। ये विचारधाराएं नीति निर्माण, कक्षा की प्रक्रियाओं और पाठ्यक्रम विकास को सीधे प्रभावित करती हैं।

राज्य शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ केंद्रीकरण और स्थानीय नियंत्रण के बीच संतुलन साधना आवश्यक होता है। यह वित्तीय व्यवस्था, उत्तरदायित्व की प्रणाली और नीति के क्रियान्वयन को निर्धारित करता है। राजनीतिक निर्णय शिक्षा के परिणामों को प्रभावित करते हैं—जैसे कि शिक्षा तक पहुंच, संसाधनों का आवंटन, पाठ्यक्रम की विषयवस्तु, और मानकीकृत मूल्यांकन—जो अंततः सामाजिक गतिशीलता और समानता को प्रभावित करते हैं।उदारवाद उदारवाद शिक्षा को व्यक्ति की स्वतंत्रता, विकास, और सामाजिक दायित्व का माध्यम मानता है। यह विचारशील, संवेदनशील और सक्रिय नागरिकों के निर्माण की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है।शिक्षा में व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर बल देता है, समान शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देता है, आलोचनात्मक सोच और विविध दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करता है। इसके उदाहरण चार्टर स्कूल और प्रगतिशील शिक्षा हैं।रूढ़िवाद रूढ़िवाद शिक्षा को एक ऐसा माध्यम मानता है जो समाज की स्थिरता और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है। हालाँकि, आधुनिक शिक्षा में इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हैं। पारंपरिक मूल्यों और तरीकों पर केंद्रित होता है, मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षण का समर्थन करता है, अनुशासन और चरित्र विकास पर बल देता है। इसके उदाहरण हैं—कॉमन कोर मानक और स्कूल यूनिफॉर्म।समाजवाद भारत का संविधान भी समाजवाद की भावना से प्रेरित है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, सर्वशिक्षा अभियान, नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा की बात—इन सबमें समाजवाद की छाया दिखती है। मुफ्त और सार्वभौमिक शिक्षा की वकालत करता है, सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देता है और शैक्षिक असमानताओं को कम करने का लक्ष्य रखता है। इसके उदाहरण हैं—सरकारी स्कूल और मुफ्त कॉलेज शिक्षा।

प्रमुख अंतर सरकार की भूमिका (नियंत्रण और वित्तपोषण), पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और डिज़ाइन के दृष्टिकोण, तथा शैक्षिक विकल्प और निजीकरण (जैसे वाउचर योजनाएं, होम स्कूलिंग) के प्रति दृष्टिकोण में देखे जा सकते हैं। यह विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि शिक्षा न केवल ज्ञान का माध्यम है, बल्कि यह समाज के राजनीतिक और वैचारिक ढांचे का प्रतिबिंब भी है।

***किवर्ड्स**: राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समाजवाद, नवउदारवाद, राष्ट्रवाद, शिक्षा प्रशासन, भारत.*

परिचय

शिक्षा नीति किसी भी देश की राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक दिशा का एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक होती है। एक लोकतांत्रिक और विविधताओं से परिपूर्ण देश जैसे भारत में, जहाँ राजनीतिक परिवर्तन प्रायः होते रहते हैं, सामाजिक संरचनाएँ निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और वैचारिक मानदंडों में बदलाव आता रहता है, वहाँ शिक्षा नीतियाँ सदैव शासक सरकार की विचारधारा से प्रभावित रही हैं और अनेक बार उन्हें पुनः स्वरूपित भी किया गया है। चाहे वह समानता और शिक्षा की पहुँच को बढ़ावा देने के लिए हो, राष्ट्रीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने हेतु हो, अथवा शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए, राजनीतिक विचारधाराएँ शैक्षिक उद्देश्यों, विषयवस्तु, विधियों और लक्षित लाभार्थियों को आकार प्रदान करती हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की वैचारिक आधारभूमि की समीक्षा की गई है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक की नीतियाँ सम्मिलित हैं।

सरकारें नीति निर्माण के माध्यम से शिक्षा के लिए वित्त पोषण मॉडलों को तैयार करती हैं और उन्हें प्रभावित करती हैं। वे शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण को शिक्षा से संबंधित नीतियों की आवश्यकताओं के अनुसार रूप देती हैं, विद्यालयों के अधोसंरचना चयन और वाउचर कार्यक्रमों (जैसे "नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड", "रेस टू द टॉप") को भी प्रभावित करती हैं।

शैक्षिक प्रथाएँ कक्षा प्रबंधन शैलियों को प्रभावित करती हैं, मूल्यांकन विधियों और मानकीकृत परीक्षणों का निर्धारण करती हैं, और प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में मार्गदर्शन करती हैं (जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम, प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग)।

शैक्षिक प्रथाएँ यह तय करती हैं कि कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, अनुशासन का क्या तरीका अपनाया जाएगा, और सीखने का माहौल कैसा होगा। यदि शिक्षा में *छात्र-केंद्रित* दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो कक्षा प्रबंधन सहयोगात्मक, संवादपरक और लचीला होगा।जबकि *शिक्षक-केंद्रित* पद्धति अपनाने पर अनुशासनात्मक और नियंत्रित वातावरण अधिक होगा। छात्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा — क्या केवल लिखित परीक्षाओं से, या वैकल्पिक आकलन (जैसे परियोजना कार्य, प्रस्तुति, पोर्टफोलियो) द्वारा भी।**मानकीकृत परीक्षण** (Standardized Testing) जैसे SAT, NEET, या बोर्ड परीक्षाएं एकरूपता लाते हैं लेकिन व्यक्तिगत रचनात्मकता और समझ को सीमित कर सकते हैं। प्रगतिशील शैक्षिक प्रथाओं में *फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट* और *पीयर असेसमेंट* पर जोर दिया जाता है, जो सीखने को निरंतर और रचनात्मक बनाता है। शैक्षिक प्रथाएँ यह भी निर्धारित करती हैं कि तकनीक का उपयोग केवल सामग्री की आपूर्ति तक सीमित रहेगा या वह शिक्षण-अधिगम को सक्रिय और सहभागी बनाएगी। कुछ उदाहरण:**फ्लिप्ड क्लासरूम (Flipped Classroom):** इसमें छात्र घर पर ऑनलाइन वीडियो देखकर विषय समझते हैं, और कक्षा में अभ्यास व चर्चा करते हैं। यह परंपरागत शिक्षण क्रम को उलट देता है और शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका देता है। **प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग (PBL):** इसमें छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं पर समूहों में काम करते हैं। यह समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और सहयोगी कार्य को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, शैक्षिक प्रथाएँ केवल शिक्षा की दिशा ही नहीं तय करतीं, बल्कि कक्षा के भीतर व्यवहार, मूल्यांकन की रणनीति, और तकनीकी हस्तक्षेप की गहराई को भी प्रभावित करती हैं। शिक्षकों, नीति निर्माताओं और पाठ्यचर्या योजनाकारों को इन पहलुओं को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण रूप से अपनाना आवश्यक है।

पाठ्यक्रम विकास शिक्षा प्रणाली की मूल संरचना को निर्धारित करता है और यह तय करता है कि छात्रों को क्या, कैसे और क्यों पढ़ाया जाएगा। यह न केवल विषयों की रूपरेखा तैयार करता है, बल्कि पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-सामग्रियों के चयन में भी मार्गदर्शन करता है। जिन विषयों और अवधारणाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, वे समाज की सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैचारिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। कई बार पाठ्यक्रम में कुछ विषयों को विवादास्पद मानते हुए जानबूझकर बाहर कर दिया जाता है, जैसे जाति, लिंग, धर्म या राजनीतिक इतिहास से जुड़े मुद्दे, जबकि कुछ विषयों को विशेष रूप से शामिल किया जाता है ताकि राष्ट्रीय पहचान, वैज्ञानिक सोच या तकनीकी दक्षता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम विकास यह भी निर्धारित करता है कि किन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाए — जैसे आज के दौर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिससे मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी जा रही है। इस प्रकार, पाठ्यक्रम केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि यह भी एक वैचारिक दस्तावेज होता है जो समाज की दिशा तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विचारधारात्मक प्रभाव शिक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं को गहराई से प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से वे क्षेत्र जो सामाजिक, नैतिक, और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े होते हैं। ये प्रभाव पाठ्यक्रम की विषयवस्तु, प्रस्तुति, प्राथमिकता, और व्याख्या के तरीके को आकार देते हैं। विभिन्न सरकारें, राजनीतिक दल और सामाजिक समूह अपनी विचारधारा के अनुरूप शैक्षिक दिशा तय करने का प्रयास करते हैं, जिससे शिक्षा केवल ज्ञान का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक निर्माण का एक सशक्त उपकरण बन जाती है।

लिंग शिक्षा और स्वास्थ्य पाठ्यक्रम विशेष रूप से विचारधारा के प्रभाव में आते हैं। *"Abstinence-only"* (केवल संयम आधारित) कार्यक्रम अमेरिका जैसे देशों में ऐसे ही प्रभाव का उदाहरण हैं, जहाँ रूढ़िवादी विचारधारा के प्रभाव में छात्रों को केवल विवाहपूर्व संयम की शिक्षा दी जाती है, जबकि यौनिकता, गर्भनिरोध, और लैंगिक विविधता जैसे विषयों को या तो अनदेखा किया जाता है या

वर्जित बना दिया जाता है। अध्ययन बताते हैं कि इस प्रकार के पाठ्यक्रमों से छात्रों को सम्यक् और वैज्ञानिक जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे व्यवहारिक ज्ञान की कमी होती है (Santelli et al., 2006, *Journal of Adolescent Health*).

इतिहास और समाज अध्ययन की सामग्री भी अत्यधिक वैचारिक प्रभावों के अधीन रहती है। उदाहरणस्वरूप, अमेरिका में *"The 1619 Project"* को लें, जिसे *The New York Times* द्वारा आरंभ किया गया था और जिसने अमेरिका के इतिहास में अफ्रीकी-अमेरिकी दासता को केंद्रीय भूमिका में रखने की कोशिश की। इस परियोजना को प्रगतिशील विचारधारा का समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन इसे रूढ़िवादी हलकों में विवादास्पद माना गया, और कई राज्यों ने इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की। इसी तरह भारत में इतिहास लेखन के संदर्भ में यह देखा गया है कि विभिन्न सरकारें शासन में आने पर इतिहास की किताबों की सामग्री में संशोधन करती रही हैं, जिससे इतिहास का प्रस्तुतिकरण अक्सर एक पक्षीय बन जाता है (Thapar, 2009).

पर्यावरण शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों को लेकर भी विचारधाराएँ मार्गदर्शन करती हैं। वैज्ञानिक समुदाय द्वारा जलवायु परिवर्तन को वैश्विक संकट माना गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक समूह इसे या तो कम महत्व देते हैं या इसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। इस प्रकार, कुछ देशों या राज्यों में पर्यावरण शिक्षा में जलवायु संकट की स्पष्ट चर्चा होती है जबकि अन्य में यह विषय सतही रूप में पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी राज्य टेक्सास और फ्लोरिडा में जलवायु परिवर्तन के पाठ्यक्रमों में बदलाव केवल वैज्ञानिक निष्कर्षों पर आधारित नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित रहे हैं (Plutzer et al., 2016, *Science*). इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शिक्षा की वैचारिक नींव केवल नीति निर्माण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह पाठ्यक्रम की बुनियाद, विषयवस्तु की प्रस्तुति और शिक्षण के तरीकों को भी प्रभावित करती है। शिक्षा का स्वरूप किस दिशा में जाएगा — यह काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि वर्तमान में सत्ता और समाज की विचारधारा कैसी है।

शिक्षा प्रणालियों में केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण एक जटिल परंतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण विमर्श है जो यह निर्धारित करता है कि शिक्षा से संबंधित निर्णय किस स्तर पर लिए जाएँ — राष्ट्रीय (संघीय), राज्यीय या स्थानीय। इस संरचनात्मक संतुलन का सीधा प्रभाव पाठ्यक्रम के मानकीकरण, शिक्षण की गुणवत्ता, शैक्षिक समानता, और सांस्कृतिक विविधता के समावेश पर पड़ता है।

केंद्रीकरण (Centralization) वह प्रक्रिया है जिसमें शैक्षिक निर्णय—जैसे पाठ्यक्रम निर्धारण, मूल्यांकन पद्धतियाँ, शिक्षक योग्यता मानदंड—उच्च स्तरीय प्राधिकरण (जैसे राष्ट्रीय या राज्य सरकार) द्वारा तय किए जाते हैं। इसका उद्देश्य अक्सर शिक्षा की गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित करना होता है, ताकि सभी छात्रों को समान शैक्षिक अवसर मिल सकें।

एक उदाहरण **Common Core State Standards (CCSS)** हैं, जिसे अमेरिका में शिक्षा के स्तर को एक समान करने के लिए वर्ष 2010 में लागू किया गया था। यह पहल इस दृष्टिकोण से प्रेरित थी कि सभी छात्रों को चाहे वे किसी भी राज्य में क्यों न हों, समान मानकों के अनुसार पढ़ाया जाए और मूल्यांकन किया जाए (National Governors Association Center for Best Practices & Council of Chief State School Officers, 2010).

विकेंद्रीकरण (Decentralization) इसके विपरीत, शिक्षा से जुड़े निर्णयों को स्थानीय स्तर — जैसे ज़िला शिक्षा कार्यालय या स्कूल बोर्ड — को सौंपता है। यह दृष्टिकोण स्थानीय जरूरतों, सांस्कृतिक मूल्यों और समुदाय की अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षा को अनुकूल बनाने की कोशिश करता है।

अमेरिका में **स्थानीय स्कूल बोर्ड** इस प्रणाली का उदाहरण हैं, जो स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, और नीति निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। यह मॉडल लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, लेकिन कभी-कभी इससे असमानता या गुणवत्ता में अंतर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है (Wirt & Kirst, 2005).

भारत जैसे देश में भी यह द्वंद्व मौजूद है। राष्ट्रीय स्तर पर *NCERT* पाठ्यचर्या और शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करता है, जबकि राज्य सरकारें *SCERT* और बोर्डों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन करती हैं। केंद्रीकरण शैक्षिक समानता और गुणवत्ता की गारंटी देता है, जबकि विकेंद्रीकरण स्थानीयता और भागीदारी को बढ़ावा देता है। एक प्रभावी शिक्षा व्यवस्था इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने में ही अपनी सफलता पाती है।

वित्त पोषण उपाय (Funding Measures)

शिक्षा प्रणालियों के संचालन के लिए सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है **वित्त पोषण**, जो अक्सर **कर-आधारित मॉडलों** (Tax-based Models) पर निर्भर करता है। अमेरिका में, विद्यालयों का वित्त मुख्यतः **संपत्ति कर (Property Tax)** के माध्यम से किया जाता है, जिससे समृद्ध क्षेत्रों के स्कूलों को अधिक धन प्राप्त होता है, जबकि गरीब इलाकों के स्कूल संसाधनों की कमी से जूझते हैं। इस असमानता को कम करने के लिए संघीय स्तर पर **Title I फंडिंग** जैसे कार्यक्रमों को लागू किया गया है, जो निम्न-आय वाले छात्रों की शैक्षिक सहायता के लिए निधियाँ प्रदान करता है (U.S. Department of Education, 2015).

भारत में भी, **समग्र शिक्षा योजना** और **आरटीई (RTE) अधिनियम, 2009** समानता लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों द्वारा शिक्षा के लिए बजट आवंटित किया जाता है। UNESCO (2021) ने यह रेखांकित किया है कि न्यायसंगत वित्त पोषण शैक्षिक गुणवत्ता सुधार का मूल आधार है।

जवाबदेही उपाय (Accountability Measures)

शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए **जवाबदेही** का निर्धारण आवश्यक है। अमेरिका में **राज्य-निर्देशित मानकीकृत परीक्षण** (Standardized Testing) और **शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली** (Teacher Evaluation Systems) इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

No Child Left Behind Act (2001) के बाद से शिक्षकों और विद्यालयों की जवाबदेही बढ़ाने हेतु छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित मूल्यांकन शुरू किया गया, जिसे **Every Student Succeeds Act (ESSA, 2015)** ने आगे सुधारते हुए लचीलापन प्रदान किया।

हालाँकि, Diane Ravitch (2010) जैसे विद्वानों ने चेताया कि केवल परीक्षण आधारित जवाबदेही से गहरी समझ और रचनात्मकता को नुकसान पहुँच सकता है। भारत में भी **शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्यांकन** अब NEP 2020 के तहत नई शिक्षण दक्षताओं और शिक्षा गुणवत्ता सूचकांकों के माध्यम से जोड़े गए हैं।

नीति क्रियान्वयन (Policy Implementation)

शिक्षा नीति केवल दस्तावेज नहीं होती, बल्कि उसका **स्थायी क्रियान्वयन** उसके प्रभाव को निर्धारित करता है। इसके लिए विधायी प्रक्रिया (Legislative Process), प्रशासनिक तंत्र, और संबंधित विभागों की स्पष्ट भूमिका तय की जाती है। अमेरिका में **Every Student Succeeds Act (ESSA)** ने संघीय नियंत्रण को घटाकर राज्यों को अपने शिक्षा सुधार की योजनाएँ तय करने की छूट दी, जिससे नीति और जमीनी कार्यान्वयन के बीच बेहतर सामंजस्य बन सका (U.S. Department of Education, 2015).

भारत में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** को लागू करने के लिए **राज्य शिक्षा बोर्ड**, **SCERT**, और **NCERT** जैसे निकायों को नई भूमिका प्रदान की गई है, जिससे **नवाचार**, **बहुभाषिकता**, और **शिक्षक प्रशिक्षण** जैसे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके (NEP, 2020).

अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएँ देशों के बीच राज्य के हस्तक्षेप में भिन्नताएँ दिखाती हैं, जो शैक्षिक परिणामों और प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव डालती हैं (जैसे फ़िनलैंड का शिक्षा प्रणाली, PISA रैंकिंग)। **अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएँ (International Comparisons)**

शिक्षा में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा और प्रकृति विभिन्न देशों में अलग-अलग होती है और यह **शैक्षिक परिणामों** और **वैश्विक प्रतिस्पर्धा** पर सीधा प्रभाव डालती है।

उदाहरण के लिए, **फ़िनलैंड** की शिक्षा प्रणाली अत्यधिक विकेंद्रीकृत है, जहाँ शिक्षकों को पाठ्यक्रम बनाने और मूल्यांकन तय करने की स्वतंत्रता होती है। वहाँ कोई मानकीकृत परीक्षा प्रारंभिक स्तर पर नहीं होती, फिर भी उनके छात्र **PISA (Programme for International Student Assessment)** जैसे अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान पर रहते हैं (Sahlberg, 2011).

इसके विपरीत, कई देशों में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली में अधिक नियंत्रण होता है, लेकिन यह कभी-कभी रचनात्मकता और स्वतंत्र निर्णय क्षमता को सीमित कर देता है। UNESCO (Global Education Monitoring Report, 2020) के अनुसार, जो देश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीति और पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रदान करते हैं, वे दीर्घकालिक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं।

राजनीतिक विचारधारा और शैक्षिक प्रभाव
समाजवादी प्रभाव

मुफ्त, सार्वभौमिक शिक्षा की वकालत की गई।
कोठारी आयोग (1964–66) जैसी नीतियों ने असमानताओं को समाप्त करने के लिए सामान्य स्कूल प्रणाली की सिफारिश की।
शिक्षा को एक सार्वजनिक भलाई के रूप में देखा गया, जिसे राष्ट्र निर्माण के विचार द्वारा प्रेरित किया गया।
1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारत ने जवाहरलाल नेहरू और अन्य सरकारों के नेतृत्व में समाजवादी दिशा अपनाई, जिसने स्वतंत्रता के बाद से 1980 के दशक तक शिक्षा नीति को गहरे प्रभावित किया। शिक्षा को राष्ट्र निर्माण, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा गया। राज्य ने शिक्षा की आपूर्ति और नियमन में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिससे सरकारी वित्त पोषित स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का विस्तार हुआ। समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए।
इस युग की एक विशेषता यह थी कि पांच साल की योजनाओं के ढांचे के भीतर शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, जो 1951 से शुरू हुआ। इन योजनाओं में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता, और व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गई। प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IITs, IIMs, NCERT (1961), और UGC (1956) की स्थापना ने सरकार की सार्वजनिक शिक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया। कोठारी आयोग (1964–66) ने नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने सामान्य स्कूल प्रणाली अपनाने, 10+2+3 शैक्षिक संरचना, और शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की सिफारिश की।
1968 में, सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करना, और शिक्षा को राष्ट्रीय और सामाजिक एकता प्राप्त करने के एक साधन के रूप में प्रस्तुत करना था। हालांकि इन समाजवादी नीतियों ने समावेशी और समान शिक्षा की नींव रखी, लेकिन

अवसंरचना की कमी, शिक्षकों की कमी, और गुणवत्ता से संबंधित समस्याएँ बनी रहीं। इसके बावजूद, इस दौर ने एक ऐसे शिक्षा तंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो समानता और राज्य की जिम्मेदारी पर आधारित था।

नवउदारवाद प्रभाव

शिक्षा के निजीकरण और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया।

सार्वजनिक खर्च को कम किया गया और बाजार-उन्मुख कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया।

निजी संस्थानों का विकास हुआ, लेकिन इससे शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सामाजिक असमानताएँ बढ़ गईं।

1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत ने भारत की विकास दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जो समाजवादी मॉडल से नवउदारवादी विचारधारा की ओर बढ़ा। नवउदारवाद निजीकरण, निरवर्तन, सरकारी खर्च में कमी, और मुक्त बाजार पर बल देता है। इस वैचारिक बदलाव ने शिक्षा नीति को गहरे प्रभावित किया। राज्य ने शिक्षा में अपनी सीधी भूमिका को कम करना शुरू किया और निजी भागीदारी और निवेश को बढ़ावा दिया, चाहे वह स्कूल, उच्च शिक्षा, या तकनीकी शिक्षा हो। शिक्षा को धीरे-धीरे एक वस्तु और व्यक्तिगत निवेश के रूप में देखा जाने लगा, न कि एक सार्वजनिक भलाई के रूप में। इससे निजी संस्थानों, जैसे निजी विश्वविद्यालयों, कोचिंग केंद्रों, और अंतरराष्ट्रीय सहयोगों का विकास हुआ। नीतियाँ अब कौशल विकास, रोजगार क्षमता, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर ध्यान केंद्रित करने लगीं। हालांकि इन सुधारों ने शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से पहुंच बढ़ाई, लेकिन इसने शिक्षा के अवसरों और गुणवत्ता के संदर्भ में समृद्ध और गरीब के बीच असमानता को बढ़ा दिया। शिक्षा अब बाजार-उन्मुख होती गई, जिसमें प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और परिणाम-आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया। हालांकि नवउदारवादी सुधारों ने भारतीय शिक्षा को आधुनिकीकरण और वैश्विक एकीकरण प्रदान किया, लेकिन इसने वाणिज्यीकरण, समानता, और राज्य की भूमिका के घटते प्रभाव को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न कीं।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद प्रभाव

राष्ट्रवादी सरकारों के तहत पाठ्यक्रम संशोधन ने भारतीय संस्कृति, धरोहर और इतिहास की वैचारिक कथाओं को प्रतिबिंबित किया।

नैतिक शिक्षा, क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक गर्व पर बढ़ती हुई जोर।

आलोचकों का कहना है कि इससे ऐतिहासिक और सामाजिक विज्ञान शिक्षा में बहिष्कार या पुनरावलोकन हो सकता है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पहचान राजनीति ने शैक्षिक नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, विशेष रूप से पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और शिक्षा के समग्र उद्देश्यों को आकार देने में। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने पर जोर देता है, जो देश की पारंपरिक संस्कृति, मूल्यों और धरोहर में निहित है। यह दृष्टिकोण अक्सर शैक्षिक तंत्र में स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों, भाषाओं और ऐतिहासिक कथाओं की प्राथमिकता पुनः स्थापित करने की कोशिश करता है। इसके परिणामस्वरूप, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रभावित शैक्षिक नीतियाँ स्कूल की किताबों को राष्ट्रीय गर्व को प्रदर्शित करने, प्राचीन सभ्यताओं की महिमा बढ़ाने, और ऐतिहासिक घटनाओं को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से फिर से व्याख्यायित करने के लिए संशोधित कर सकती हैं। दूसरी ओर, पहचान राजनीति विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, भाषाई, या जाति-आधारित समूहों के अधिकारों और आवाजों को पहचानने और प्रमाणित करने से संबंधित है। इसके प्रभाव को क्षेत्रीय इतिहास, जनजातीय ज्ञान प्रणालियों की समावेशिता, और मातृभाषा शिक्षा या पाठ्यक्रम सामग्री में प्रतिनिधित्व की मांगों में देखा जा सकता है। जबकि ये बदलाव हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बना सकते हैं और सांस्कृतिक समावेशिता को बढ़ावा दे सकते हैं, वे शिक्षा के राजनीतिकरण, सांप्रदायिक तनावों और ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता पर बहसों का कारण भी बन सकते हैं। इस प्रकार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पहचान राजनीति का मिलाजुला प्रभाव शैक्षिक नीतियों के निर्माण में एक जटिल भूमिका निभाता है, जो एकता और विविधता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।

प्रगतिशील और समावेशी प्रभाव

समानता, समावेशिता, और शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षाशास्त्र पर जोर।

NEP 2020 में मातृभाषा में शिक्षा, लचीला पाठ्यक्रम, और डिजिटल शिक्षा जैसे तत्व शामिल हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा को स्वदेशी ज्ञान और समानता लक्ष्यों के साथ संतुलित करने का प्रयास।

प्रगतिशील और समावेशी दृष्टिकोणों का शैक्षिक नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से 21वीं सदी में। इन दृष्टिकोणों ने शिक्षा के ध्यान केंद्र को कठोर, समान्य प्रणालियों से बदलकर अधिक लचीले, शिक्षार्थी-केंद्रित ढाँचों की ओर मोड़ दिया है। शैक्षिक नीतियाँ अब व्यक्तिगत अध्ययन की जरूरतों को पूरा करने, सक्रिय भागीदारी, आलोचनात्मक सोच और सहयोगी सीखने को बढ़ावा देने पर जोर देती हैं। उदाहरण के लिए, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है और छात्रों को उनके रुचियों और क्षमताओं के अनुसार विषय चुनने की अनुमति देती है।

इन दृष्टिकोणों का एक प्रमुख पहलू समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। शैक्षिक नीतियाँ अब सामाजिक-आर्थिक, लिंग, विकलांगता, और सांस्कृतिक असमानताओं के कारण उत्पन्न हुए अंतर को पाटने का लक्ष्य रखती हैं। इसके परिणामस्वरूप विशेष समूहों के लिए आरक्षण, छात्रवृत्तियाँ और विशेष प्रावधानों जैसी सकारात्मक कार्रवाइयों की शुरुआत हुई है। भारत में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 एक महत्वपूर्ण नीति है, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है और निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सीटें आरक्षित करता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ने का है, जहाँ विकलांग और गैर-विकलांग बच्चे नियमित कक्षाओं में एक साथ पढ़ते हैं। विशेष शिक्षा से यह बदलाव

समावेशी शिक्षाशास्त्र और सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन को अपनाने वाली नीतियों को प्रभावित करता है। भारत में संशोधित विकलांग व्यक्तियों अधिनियम (2016) जैसे कानून समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करते हैं, चाहे उनकी क्षमता कोई भी हो।

इसके अलावा, प्रगतिशील और समावेशी नीतियाँ शिक्षार्थियों के समग्र विकास पर जोर देती हैं। अब शिक्षा केवल शैक्षिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है; इसमें सामाजिक-भावनात्मक सीख, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक कल्याण और मूल्य शिक्षा शामिल हैं। पाठ्यक्रमों को छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।

ये दृष्टिकोण सामुदायिक और अभिभावक भागीदारी के महत्व को भी उजागर करते हैं। विकेंद्रीकृत शासन मॉडल स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) के माध्यम से स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि समावेशी शिक्षा नीतियाँ अभिभावक जागरूकता और सामुदायिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा, सभी छात्रों, विशेष रूप से विकलांग छात्रों, के लिए शिक्षा में पहुँच और व्यक्तिगत अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। नीतियाँ अब डिजिटल साक्षरता, सहायक प्रौद्योगिकियों, और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का समर्थन करती हैं।

शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास इन दृष्टिकोणों का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम है। शैक्षिक नीतियाँ समावेशी विधियों और शैक्षिक नवाचारों में सेवा में शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर देती हैं ताकि वे विविध कक्षाओं को प्रबंधित करने के लिए तैयार रहें। अंत में, मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार किया गया है ताकि वे रटना आधारित शिक्षा से हटकर कौशल, रचनात्मकता, और ज्ञान के आवेदन पर ध्यान केंद्रित करें।

कुल मिलाकर, प्रगतिशील और समावेशी शैक्षिक दृष्टिकोणों ने नीतियों को फिर से आकारित किया है ताकि अधिक समान, लचीले और शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा प्रणालियाँ बनाई जा सकें जो विविधता को महत्व देती हैं, समावेश को बढ़ावा देती हैं और छात्रों को आधुनिक दुनिया की मांगों के लिए तैयार करती हैं।

भारत में प्रमुख शिक्षा नीतियों और वैचारिक शिक्षा का विश्लेषण

1-राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) स्वतंत्र भारत की पहली व्यापक शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आकार लिया था। इसका उद्देश्य सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना था, चाहे वह जाति, धर्म, स्थान, या लिंग के आधार पर हो। इस नीति ने सामान्य स्कूल प्रणाली (CSS) का समर्थन किया, ताकि अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानताओं को समाप्त किया जा सके। इसने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामान्य नागरिकता और संस्कृति की भावना उत्पन्न करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था तीन-भाषा सूत्र का परिचय, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, और क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन की सिफारिश की गई थी, ताकि बहुभाषी देश में भाषाई समरसता को बढ़ावा मिल सके। नीति में शिक्षा में सरकारी निवेश को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य था, जो समय के साथ अब तक पूरा नहीं हो सका। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया गया, शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, और ड्रॉपआउट दर को कम करने की आवश्यकता को पहचाना गया। हालांकि, नीति के उद्देश्य दूरदर्शी थे, लेकिन अवसंरचना और धन की कमी के कारण कार्यान्वयन सीमित रहा।

2-राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसे मजबूत केंद्रीकृत योजना और समाजवादी शासन के दौरान पेश किया गया था, समानता, पहुंच और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। इस नीति ने यह स्वीकार किया कि कुछ हाशिए पर रहने वाले समूहों—जैसे अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, महिलाएँ और अल्पसंख्यक—के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और शैक्षिक अंतर को पाटने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की योजना बनाई गई। इस नीति के तहत एक महत्वपूर्ण पहलू था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी ढांचे को सुधारना था, ताकि आवश्यक शैक्षिक सामग्री और प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक हों। नीति ने वयस्क शिक्षा पर भी जोर दिया, जो सरकार की निरक्षर वयस्कों की विशाल जनसंख्या को लेकर चिंता को दर्शाता है, और जन साक्षरता अभियानों की शुरुआत की। महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम सुधार किए गए, ताकि लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। नीति में शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा में शोध, और मीडिया एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया। साथ ही, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) जैसी संस्थाएँ स्थापित की गईं, ताकि शिक्षकों को जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा सके। हालांकि, नीति की मंशा प्रगतिशील थी, लेकिन यह शीर्ष-से-नीचे दृष्टिकोण बनाए रखती थी, जो केंद्रीकृत योजना और नौकरशाही कार्यान्वयन पर अत्यधिक निर्भर थी, जिससे कभी-कभी स्थानीय नवाचार और अनुकूलन में बाधा उत्पन्न होती थी।

3-राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत करती है, जिसमें नवउदारवादी, राष्ट्रवादी और प्रगतिशील विचारधाराओं का समावेश किया गया है। यह नीति 21वीं सदी के कौशल की महत्वता को पहचानती है और भारतीय संस्कृति और मूल्यों में मजबूत आधार के साथ एक समग्र, लचीला, और बहुविषयक शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव करती है। यह नीति विद्यालय स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देती है, ताकि शैक्षिक अध्ययन और रोजगार तैयार होने की खाई को पाटा जा सके। यह बहुभाषावाद का समर्थन करती है, और कम से कम कक्षा 5 तक, और आदर्श रूप से कक्षा 8 तक, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश करती है, ताकि समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार हो सके।

NEP 2020 शैक्षिक प्रौद्योगिकी (EdTech) को भविष्य की शिक्षा के मुख्य चालक के रूप में स्वीकार करती है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन संसाधन और मिश्रित लर्निंग पद्धतियों को बढ़ावा देती है। यह पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में सुधार की शुरुआत करती है, जैसे 5+3+3+4 संरचना, दक्षता-आधारित शिक्षा, और अनुभवात्मक और खोज-आधारित शिक्षण पर जोर दिया गया है। नीति स्थानीय जड़ों के साथ वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिससे छात्र राष्ट्रीय विकास और वैश्विक नागरिकता दोनों के लिए तैयार हो सकें। उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना, और कला, विज्ञान और व्यावसायिक धारा के बीच कठोर सीमाओं को समाप्त करना इसकी नवउदारवादी प्रवृत्तियों को दर्शाता है। साथ ही, इसकी भारतीय ज्ञान प्रणालियों, संस्कृत और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर देना राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को संकेत करता है। प्रगतिशील पहलुओं में समानता, समावेशिता, और लिंग संवेदनशीलता पर जोर दिया गया है। NEP 2020 एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, हालांकि इसके लिए वित्तपोषण, डिजिटल विभाजन, और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के संदर्भ में कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

सरकारों की वैचारिक दिशा शैक्षिक दिशा और वितरण पर गहरा प्रभाव डालती है। समाजवादी मॉडल राज्य की जिम्मेदारी और सार्वजनिक कल्याण पर जोर देते हैं, जबकि नवउदारवादी एजेंडा निजीकरण और आर्थिक उपयोगिता पर बल देते हैं। राष्ट्रीयतावादी विचारधाराएँ अक्सर पाठ्यक्रम सामग्री को निर्धारित करती हैं, जबकि प्रगतिशील नीतियाँ सीखने की स्वायत्तता, समावेशिता और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देती हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति में लगातार बदलाव का मतलब है कि शिक्षा अक्सर वैचारिक संघर्ष का स्थल बन जाती है, जो इसकी निरंतरता और स्थिरता को प्रभावित करता है।

भारत में शिक्षा से संबंधित नीतियों के स्वरूप को तय करने में राजनीतिक विचारधाराओं का योगदान

1. **राजनीतिक विचारधाराओं की परिभाषा और उनका शिक्षा नीति-निर्माण में प्रभाव:** राजनीतिक विचारधारा एक विश्वासों, मूल्यों और सिद्धांतों के सेट को संदर्भित करती है जो सरकार या शासक दल की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि को आकार देती है। शिक्षा के संदर्भ में, राजनीतिक विचारधाराएँ यह निर्धारित करती हैं कि नीतियाँ कैसे तैयार, कार्यान्वित और प्राथमिकता प्राप्त करती हैं। वे शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करती हैं—चाहे वह राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, या सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना हो। शिक्षा नीति-निर्माण, इसलिए, एक तटस्थ प्रक्रिया नहीं है; यह स्वाभाविक रूप से शासक विचारधारा से प्रभावित होती है, जो पाठ्यक्रम सामग्री से लेकर संसाधन आवंटन, शासन संरचनाओं, और यहां तक कि शिक्षा की भाषा तक को प्रभावित करती है।

2. **भारतीय शिक्षा नीतियों का विश्लेषण और उनकी वैचारिक नींव**: भारत की प्रमुख शिक्षा नीतियाँ—NPE 1968, NPE 1986, और NEP 2020—प्रत्येक अपनी-अपनी समय की प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं को दर्शाती हैं। 1968 की नीति, स्वतंत्रता के बाद समाजवादी युग में तैयार की गई, समानता और राष्ट्रीय एकता पर जोर देती थी, सामान्य स्कूल प्रणाली और तीन-भाषा सूत्र के माध्यम से भाषाई समरसता का समर्थन करती थी। 1986 की नीति, केंद्रीकृत योजना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर बढ़ती हुई फोकस के दौरान, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और वयस्क शिक्षा कार्यक्रम जैसे लक्षित हस्तक्षेपों का परिचय देती है, जो राज्य की जिम्मेदारी और समावेशन के समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप थे। इसके विपरीत, NEP 2020 नवउदारवादी, राष्ट्रवादी और प्रगतिशील विचारधाराओं का मिश्रण है। यह व्यावसायिकता और निजीकरण जैसे बाजार-आधारित सुधारों को बढ़ावा देती है, भारतीय ज्ञान प्रणालियों के पुनरुद्धार के माध्यम से राष्ट्रीयतावादी विचारों का समर्थन करती है, और अनुभवात्मक शिक्षा और लचीले पाठ्यक्रम जैसे प्रगतिशील शिक्षाशास्त्र को प्रोत्साहित करती है।

3. **शैक्षिक पहुँच, समानता और गुणवत्ता पर वैचारिक बदलावों के प्रभाव का विश्लेषण:** हर वैचारिक परिवर्तन शैक्षिक के मुख्य लक्ष्यों—पहुँच, समानता और गुणवत्ता—पर विभिन्न प्रभाव डालता है। 1968 और 1986 की समाजवादी नीतियाँ सार्वभौमिक पहुँच और सामाजिक समानता को प्राथमिकता देती थीं, जो प्रिविलेज और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच अंतर को पाटने की कोशिश करती थीं। हालांकि, इन नीतियों को गुणवत्ता और कार्यान्वयन के मुद्दों का सामना करना पड़ा, क्योंकि संसाधन सीमित थे। NEP 2020, पाठ्यक्रम सुधार और शिक्षाशास्त्र में नवाचार के दृष्टिकोण से प्रगतिशील है, लेकिन इसके डिजिटल शिक्षा और संस्थागत स्वायत्तता पर जोर देने के कारण समानता को लेकर चिंता पैदा हुई है, जिससे शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच अंतर बढ़ सकता है। NEP 2020 का बाजार-आधारित दृष्टिकोण यदि मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ लागू न किया गया तो कम संसाधनों वाले समूहों को बाहर कर सकता है।

4. **शैक्षिक पाठ्यक्रम पर शासन और राजनीतिक प्रेरणाओं का प्रभाव**: पाठ्यक्रम डिज़ाइन और शैक्षिक शासन राजनीतिक विचारधाराओं से गहरे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, समाजवादी-झुकाव वाली नीतियाँ राष्ट्र निर्माण, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर देती थीं, जबकि NEP 2020 भारतीय ज्ञान प्रणालियों, बहुभाषावाद और भारतीय संस्कृति में निहित मूल्यों पर जोर देती है, जो एक राष्ट्रवादी एजेंडा को दर्शाता है। शासन ने पहले की नीतियों में केंद्रीकृत नियंत्रण से NEP 2020 में एक अधिक स्वायत्त, विकेन्द्रीकृत मॉडल की ओर रुख किया है, जो संस्थागत लचीलापन और नवाचार को बढ़ावा देता है। हालांकि, इस विकेन्द्रीकरण को यदि ठीक से निगरानी नहीं की गई तो यह राज्यों और संस्थानों में नीति कार्यान्वयन में असंगतियों और

असमानताओं का कारण बन सकता है। राजनीतिक प्रेरणाएँ यह भी निर्धारित कर सकती हैं कि कौन सी इतिहास, भाषाएँ या मूल्य प्रणालियाँ पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्रियों में प्रमुख या गौण होंगी, जो भविष्य पीढ़ियों की वैचारिक दिशा को प्रभावित करेंगी।

निष्कर्ष

राजनीतिक विचारधाराएँ केवल पृष्ठभूमि कारक नहीं हैं—वे राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के विकास, प्राथमिकताओं और परिणामों को सक्रिय रूप से आकार देती हैं। भारतीय संदर्भ में, समाजवाद, राष्ट्रीयता और नवउदारवाद का प्रभाव नीतियों के विकास के दशकों में देखा जा सकता है। इन वैचारिक प्रभावों की गहरी समझ नीतियाँ बनाने के लिए आवश्यक है जो समान, समावेशी और लोकतांत्रिक रूप से उत्तरदायी हों। भारतीय शिक्षा नीति का विकास यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि शिक्षा राजनीति से अलग नहीं है। राजनीतिक विचारधाराएँ केवल शैक्षिक लक्ष्यों के निर्माण को ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि वे उन तरीकों को भी प्रभावित करती हैं जिनके माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। जैसे-जैसे भारत समकालीन शैक्षिक सुधारों की दिशा में अग्रसर हो रहा है, वैचारिक नींव के प्रति एक आलोचनात्मक जागरूकता आवश्यक है ताकि पाठ्यक्रम नवाचार और शासन सुधार में प्रगति समान रूप से समानता, समावेशिता और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता से मेल खा सके। दशकों में, भारत में शिक्षा नीतियाँ बदलती राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं और वैश्विक प्रभावों को दर्शाती हुई विकसित हुई हैं। जहां 1968 की नीति ने समानता और राष्ट्रीय एकता की नींव रखी, वहीं 1986 की नीति ने केंद्रीकृत रणनीतियों के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों और वयस्क शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। इसके विपरीत, NEP 2020 आर्थिक उदारीकरण, सांस्कृतिक गर्व और शैक्षिक नवाचार का संतुलन बनाकर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। एक साथ, ये नीतियाँ भारत की समावेशी, समान और गतिशील शैक्षिक परिप्रेक्ष्य की ओर यात्रा को दर्शाती हैं, हालांकि इसके कार्यान्वयन में निरंतर और संदर्भ-संवेदनशील प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है।

संदर्भ

Apple, M. (2000). Official Knowledge: Democratic Education in a Conservative Age. Routledge.

Dreze, J., & Sen, A. (2013). An Uncertain Glory: India and its Contradictions. Penguin.

Giroux, H. (1983). Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition.

Kumar, K. (1991). Political Agenda of Education. Sage.

Tilak, J.B.G. (2004). Public Expenditure on Education in India. Economic and Political Weekly, 39(9).

Ministry of Education (1968, 1986, 2020). National Policy on Education. Government of India.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****